



INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI

F. No. 21-14/2010-CDN

Dated 11.10.2012

**ENDORSEMENT**

Department of Personnel, Public Grievances & Pensions(DOPPW), Government of India, New Delhi has issued O.M. No. 42/13/2012-P&PW(G) dated 4.10.2012 regarding – Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 1.7.2012. The above mentioned O.M. is being uploaded on the ICAR Web-Site [www.icar.org.in](http://www.icar.org.in) for information and further guidance.

(J.N. Bhagat)  
Under Secretary (GAC)

**DISTRIBUTION :-**

1. All Directors/Project Directors of all ICAR Institutes/National Research Centres/Project Coordinators/Coordinated Research Projects/Zonal Project Coordinators/Bureaux
2. Sr.PPS to DG, ICAR/PPS to Secretary, ICAR/PPS to FA (DARE).
3. Chairman ASRB/ND, NAIP/ Project Director(DKMA), Pusa, New Delhi.
4. Shri Hans Raj, ISO, (DKMA) KAB-I for putting in the ICAR Web-Site.
5. All Officers/Sections at ICAR Krishi Bhawan/KAB-I/II & NASC Complex.
6. Secy. (Staff Side), CJSC, National Research Centre on Meat, Chengicherla, Hyderabad – 500 039
7. Secy. (Staff Side), HJSC, ICAR, KAB-II
8. Guard file/Spare copies

F. No. 42/13/2012-P&PW(G)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3<sup>rd</sup> Floor, Lok Nayak Bhavan,  
Khan Market, New Delhi - 110003  
Date: 4<sup>th</sup> October, 2012

### OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners - Revised rate effective from 1.7.2012.**

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/13/2012-P&PW(G) dated 4<sup>th</sup> April, 2012 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief (DR) payable to Central Government pensioners/family pensioners shall be enhanced from the existing rate of 65% to 72% w.e.f. 1<sup>st</sup> July, 2012.

2. These orders apply to (i) All Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners (ii) The Armed Forces Pensioners, Civilian Pensioners paid out of the Defence Service Estimates, (iii) All India Service Pensioners (iv) Railway Pensioners and (v) The Burma Civilian pensioners/family pensioners and pensioners/families of displaced Government pensioners from Pakistan, who are Indian Nationals but receiving pension on behalf of Government of Pakistan and are in receipt of ad-hoc ex-gratia allowance of Rs. 3500/- p.m. in terms of this Department's OM No. 23/1/97-P&PW(B) dated 23.2.1998 read with this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 15.9.2008.

3. Central Government Employees who had drawn lumpsum amount on absorption in a PSU/Autonomous body and have become eligible to restoration of 1/3<sup>rd</sup> commuted portion of pension as well as revision of the restored amount in terms of this Department's OM No. 4/59/97-P&PW (D) dated 14.07.1998 will also be entitled to the payment of DR @ 72% w.e.f. 1.7.2012 on full pension i.e. the revised pension which the absorbed employee would have received on the date of restoration had he not drawn lumpsum payment on absorption and Dearness Pension subject to fulfillment of the conditions laid down in para 5 of the O.M. dated 14.07.98. In this connection, instructions contained in this Department's OM No.4/29/99-P&PW (D) dated. 12.7.2000 refer.

4. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

Contd..2..

*Sy. P. B. 1*

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended vide this Department's OM No. F. No. 38/88/2008-P&PW(G) dated 9<sup>th</sup> July, 2009. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension, will remain unchanged.

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

8. The offices of Accountant General and Authorised Public Sector Banks are requested to arrange payment of relief to pensioners etc. on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21<sup>st</sup> May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

9. In their application to the pensioners/family pensioners belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders issue after consultation with the C&AG.

10. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure conveyed vide their OM No. 1(4)/EV/2004 dated 4<sup>th</sup> October, 2012.

11. Hindi version will follow.



( S. P. Kakkar )

Under Secretary to the Government of India

To,

All Ministries/Departments of the Government of India/Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.

Please visit this Department's website  
<http://www.pensionersportal.gov.in> for the orders on pension matters including above orders.

फा0 सं0. 42/13/2012-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी)

भारत सरकार

कर्मिक, लोक शिक्कयत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

\*\*\*\*\*

तीसरा तल, लोक नायक भवन,  
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 04 अक्टूबर, 2012

कार्यालय जापन

**विषय : केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति**  
**- संशोधित दर दिनांक 1.7.2012 से लागू ।**

अर्धहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 4.4.2012 के कार्यालय जापन सं0 42/13/2012-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/ कुटुम्ब पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत दिनांक 1.7.2012 से मौजूदा 65% से बढ़ाकर 72% कर दी जाएगी ।

2. ये आदेश (i) सभी सिविलियन केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों (ii) रक्षा सेवा एस्टीमेट से भुगतान किए जाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, सिविलियन पेंशनभोगियों, (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों, (iv) रेलवे पेंशनभोगियों तथा (v) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों जो भारतीय नागरिक हैं परन्तु जिन्हें पाकिस्तान सरकार के सौजन्य से पेंशन प्राप्त हो रही है तथा जो इस विभाग के दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय जापन संख्या 23/3/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू(बी) के साथ पठित दिनांक 23.2.1998 के कार्यालय जापन सं0 23/1/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू (बी) के अनुसार 3500/- रूपए प्रतिमाह तदर्थ अनुग्रह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, पर लागू होंगे ।

3. केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्थायित्त निकाय में आमेहन होने पर एकमुश्त धनराशि आहरित किया था तथा जो इस विभाग के दिनांक 14.07.1998 के कार्यालय जापन सं0 4/59/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू (डी) के अनुसार पेंशन के 1/3 संशोधित भाग की बहाली तथा बहाल की गई धनराशि के संशोधन के लिए अर्ह हो गए थे, वे पूर्ण पेंशन पर अर्थात् संशोधित पेंशन जो कि विलयित कर्मचारी बहाली के दिन प्राप्त करता यदि वह विलयन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त न किया होता, इस विभाग के दिनांक 14.07.98 के कार्यालय जापन के पैरा 5 में दी गई शर्तों के पूरा होने के अधीन 1.1.2012 से 72% महंगाई राहत के भुगतान के हक्दार होंगे । इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.7.2000 के का0 जापन सं0 4/29/99-पी एण्ड पी डब्ल्यू(डी) में निहित अनुदेश देखें ।

क्रमशः...2..

सूचक 121 अनु

4. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

5. नौकरी पेशा कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा पुनर्नियोजित केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के मामले में महंगाई राहत को अभिशासित करने वाले अन्य प्रावधान इस विभाग के दिनांक 2.7.1999 के कार्यालय जापन सं० 45/73/97-पी एण्ड पी डबल्यू(जी) तथा इस विभाग के यथा संशोधित दिनांक 9 जुलाई, 2009 के कार्यालय जापन सं० 38/88/2008-पी एण्ड पी डबल्यू (जी) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे । जहां पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है उन मामलों में महंगाई राहत के विनियमन से संबंधित प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।


6. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश न्याय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे ।

7. प्रत्येक पृथक मामले में देय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों की होगी ।

8. महालेखाकार कार्यालय एवं प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित दिनांक 23/04/1981 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पत्र सं० 528-टी ए, ॥/34-80-॥ तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहायक बैंकों तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र सं० जीएनबी सं० 2958/जी ए-64 (॥) (सी जी एल)/81 के आधार पर किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर पेंशनभोगियों आदि को राहत भुगतान का प्रबंध करें ।

9. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

10. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 के कार्यालय जापन सं० 1(4)/EV/2004 की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

  
(एस.पी.कल्कर्णी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार ।

पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट [www.pensionersportal.gov.in](http://www.pensionersportal.gov.in) देखें ।